# बजट : होटलों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने और जीएसटी दर कम करने की मांग

भास्कर संवाददाता | मुंबई

केंद्र की नई सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करेगी। देश में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को बजट में राहत की उम्मीद है। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री का जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। जीएसटी की दरों में रियायत के अलावा कौशल विकास को प्रोत्साहन तथा इस उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपाय, होटल को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने जैसी मांग उद्योग जगत ने सरकार से की है।

इस उद्योग जगत से जुड़े लोगो ने बताया की वर्तमान जीएसटी दर विश्व स्तर पर सर्वाधिक होने से पर्यटन महंगा हो गया है। जीएसटी दर कम किया जाना चाहिए। 7500/- रुपए से अधिक कमरे की दरों वाले होटलों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर 12 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखने से घरेलू और इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। होटल और रेस्तरां एसोसिएशन, पश्चिमी भारत (एचआरएडब्ल्यूआई ) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरव गांधी के अनुसार हम सभी होटलों के लिए एक समान 12 प्रतिशत जीएसटी दर और रेस्तरां शुल्क को कमरे के शुल्क से अलग करने का अनुरोध करते हैं। वर्तमान प्रणाली जहां जीएसटी कमरे की दरों के आधार पर बदलता है, इससे पर्यटकों को भ्रम पैदा होता है तथा उन्हें समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भारत को पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है , जबकि उनका जीएसटी एकल अंक में है। उच्च कर दर पर्यटकों को भारत आने से हतोत्साहित करती है, इसलिए कमरे के किराए पर जीएसटी दरों को कम किया जाना चाहिए।

## कर छूट या सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहनों पर विचार करें

10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत वाले सभी श्रेणियों के होटलों को सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दे, ताकि नई संपत्तियों पर निवेश अधिक आकर्षक हो सके, न कि उन्हें लक्जरी के रूप में वर्गीकृत किया जाए। साथ ही सरकार टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए कर छूट या सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहनों पर विचार करें। होटल और रेस्तरां के लिए एक राष्ट्रीय ई-एक्सल खिड़की निकासी प्रणाली लागत को काफी कम कर सकती है और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकती है। होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एचआरएडब्ल्यूआई) पश्चिमी भारत के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने बताया की 2047 तक 100 मिलियन विदेशी पर्यटकों का स्वागत करते हुए, भारत को एक शीर्ष वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा समर्थित एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्रतिभा की कमी को पूरा करने तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक समर्थन की भी आवश्यकता है। पर्यटन सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए सरकार को इस ओर विशेष दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

H&RA WESTERN INDIA TM
Estd : 1951